eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

# 21वीं सदी में भारतीय उच्च शिक्षाः एक विहंगम दृष्टि

**डॉ. सीमा मिश्रा**[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र, कमला नेहरू पी.जी. कॉलेज तेजगांव रायबरेली उ0प्र0

Received: 15 May 2025 Accepted & Reviewed: 25 May 2025, Published: 31 May 2025

## Abstract

उच्च शिक्षा समाज में विकास एवं परिवर्तन के लिए एक प्रमुख उपकरण है उच्च शिक्षा की भूमिका किसी भी देश के वैज्ञानिक विकास नए–नए आविष्कारों एवं सत्य की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा का विस्तार तो हुआ है परंतु आज भी समग्र रूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विसंगतियां विद्यमान है। उच्च शिक्षा जिसका लक्ष्य उच्च बौद्धिक वर्ग की स्थापना है आज बाजार का उत्पाद बनती जा रही है। उच्च शिक्षा का लगातार बढ़ता निजीकरण, निर्धारित मानकों की अनदेखी, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों एवं अभिभावकों का उच्च शिक्षा के प्रति बदलता दृष्टिकोण, आदि उच्च शिक्षा का अंश बन चुके हैं।

वर्तमान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एक सबसे बड़ी चुनौती है निःसंदेह यह गर्व की बात है कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों एवं छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि ही रही है परंतु यह प्रश्न भी उतना ही अधिक विचारणीय है कि क्या इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद भी हम उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए हैं इस विषय पर गहन चर्चा की आवश्यकता है।

**संकेत कुंजी**– गुणवत्ता, मानक, विकास, परिवर्तन, सत्य की खोज, निजीकरण,

## Introduction

शिक्षा देश के विकास का प्रमुख आधार है यदि उच्च शिक्षा का गुणात्मक विकास नहीं हुआ तो प्रशासनिक और तकनीकी प्रगति, बौद्धिक और सामाजिक प्रगति के अवरुद्ध होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉ आर.के.सिंह के अनुसार–**"देश का वैभव विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा) से संबंध होता है।**" इक्कीसवीं शताब्दी के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार उच्च शिक्षा आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति है। डॉ. जे. बी. विलनिलम का मानना है कि "शिक्षा को मानव संसाधन विकास में राष्ट्रीय निवेश के रूप में लिया जाना चाहिए।" उच्च शिक्षा ज्ञान का भण्डार भी है और ज्ञान का अर्जन भी।

उच्च शिक्षा का महत्व निर्विवाद है स्वयं विश्व बैंक ने भी सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। उच्च शिक्षा समाज में विकास एवं परिवर्तन के लिए एक प्रमुख उपकरण है। उच्च शिक्षा की भूमिका किसी भी देश के वैज्ञानिक विकास नए–नए आविष्कारों एवं सत्य की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास की रीढ़ है। उच्च शिक्षा मनुष्य को संस्कारवान और मानवीय चरित्र को उदात्तीकृत करने का सबसे कारगर हथियार है।

कार्डिनल न्यूमैन ने अपनी पुस्तक 'The Ideas of University' में लिखा है विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा संस्थान) वह स्थान है, जहां नवीन खोजें की जाती हैं। मस्तिष्क की मस्तिष्क से अंतः प्रक्रिया होती है। यह ज्ञान का मंदिर है। संसार का प्रकाश है और उन्नत पीढ़ियों की मातृ संस्था है। इसके छात्रों के स्तर को इस पर गर्व है।" किसी भी देश की सम्पन्नता या भाग्य उस देश के विश्वविद्यालयों (उच्च शिक्षा संस्थानों) से जुड़ा होता है इनके दूषित होने से सम्पूर्ण राष्ट्र दूषित हो जाता है किंतु आजकल विश्वविद्यालय का

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

तात्पर्य केवल परीक्षा लेने व डिग्री वितरित करने वाली संस्था माना जाने लगा है। वास्तव मे उच्च शिक्षा, शिक्षा का वह स्तर है जो देश को प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं उच्च शिक्षा का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय हितों को जागृत करना भी है ताकि मानव समाज और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा की जा सके। शैक्षिक संरचना और शैक्षिक पिरामिड की स्थिति के अनुसार उच्च शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। उच्च शिक्षा जिसका एक मात्र उद्देश्य ज्ञान द्वारा सत्य की खोज करना एवं पूर्णता को प्राप्त करना है।। इसके अन्तर्गत उच्चतम भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों की खोज की जाती है एवं सम्पूर्ण मानव समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक समस्याओं का हल खोजा जाता है। उच्च शिक्षा समाज की महत्वपूर्ण गतिविधियों प्रशासन, व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य, संचार, कला, साहित्य के लिए मानव संसाधन सुलभ कराती है। उच्च कोटि के वैज्ञानिक, साहित्यकार नेता तथा दार्शनिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रांगण से ही उत्पन्न होते हैं।

राधाकृष्णन आयोग (1948–49) नें उच्च शिक्षा का उद्देश्य भारत में ऐसी विभूतियों को तैयार करना, जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्य आदि क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिनिधित्व कर सकें, निर्धारित किया और कहा उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में नैतिकता, सद्व्यवहार के आदर्श, चरित्र, व्यक्तित्व एवं अनुशासन गुणों के साथ–साथ लोकतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय अनुशासन का पालन करना है। उच्च शिक्षा व्यक्तित्व विकास तथा चरित्र निर्माण का वह अतिंम औपचारिक पड़ाव है जिसको पार कर विद्यार्थी वास्तविक जीवन में प्रवेश कर एक वास्तविक सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन प्रारम्भ करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य न सिर्फ विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करना है अपितु यहाँ उसके व्यक्तित्व को अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य भी किया जाना चाहिये।

आज के विद्यार्थी को भावी नागरिक बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए शिक्षा ही एकमात्र हथियार दिखाई देता है। मूल्यों के संकट से गुजरता तथा रोजगार प्राप्ति हेतु आज का पढ़ा लिखा युवा जागरूक है जरूरत है पाठ्यक्रम को नवीनता देने की सुव्यवस्थित प्रणाली देने तथा पारदर्शी मूल्यांकन रूपी सीढी देने की ताकि ज्ञान से सरोबार विद्यार्थी समुदाय समाजोत्थान का बीड़ा उठा सके उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो एवं वे प्रतियोगिता का कड़ा मुकाबला कर सकें।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय में उसका विकास अत्यन्त त्वरित गति से हुआ है परंतु इसका विकास आदि से अन्त तक अनियोजित रहा है परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर गया है। छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा नष्ट हो गई है, शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उपस्थित हो गई है और सर्वोपरि यह शिक्षा–देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई है। परतन्त्र भारत में इस उद्देश्य के वास्तवित स्वरूप का वर्णन गुन्नार मिरडल ने किया "विश्वविद्यालय की उपाधियाँ, सरकारी नौकरियों के लिये पासपोर्ट थीं।

विद्यार्थियों को शिक्षा नौकरी के लिये, न कि जीवन के लिये तैयार करने के सीमित उद्देश्य से प्रदान की जाती थी।" जिस प्रकार उच्च शिक्षा परतन्त्र भारत में व्यक्ति को जीवन के लिये तैयार नहीं करती थी उसी प्रकार स्वतन्त्र भारत में भी नहीं करती है। इसकी पुष्टि के लिये हुमायूँ कबीर के निम्नलिखित शब्दों का अवलोकन कीजिए "बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, वह व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन के लिये तैयार नहीं करती है।"

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

**भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति–** निःसन्देह यह गर्व की बात है कि भारतीय उच्च शिक्षा विश्व में तीसरी बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उच्च शिक्षा के विकास पर केन्द्र सरकार ने काफी बल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहां देश में कुल 19 विश्वविद्यालय और 735 महाविद्यालय थे। अब उनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो चुकी है लेकिन हम अभी भी उच्च शिक्षा के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल है। पिछले 50 वर्षों में देश के विश्वविद्यालय कॉलेजों और छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यूजीसी द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार भारत में 1168 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 460 राज्य विश्वविद्यालय, 128 मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय और 430 स्व–वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, 159 अन्य राष्ट्रीय संस्थान हैं। 2024 तक 50000 कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2020–2021 जारी किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़कर 4.14 करोड़ हो गया है, जो पहली बार 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है।

2020–21 में उच्च शिक्षा में 2019–20 से 7.5% और 2014–15 से 21% की वृद्धि हुई है। 2019–20 की तुलना में 2020–21 में विश्वविद्यालयों की संख्या में 70 और कॉलेजों की संख्या में 1,453 की वृद्धि हुई है। 2019–20 में महिलाओं का नामांकन 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया है। इसमें 2014–15 से लगभग 44 लाख (28% ) की वृद्धि हुई है। दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 45.71 लाख (20.9 लाख महिलाओं सहित) है, जो 2019–20 से लगभग 7% और 2014–15 से 20% की वृद्धि है। एआईएसएचई 2020–21 रिपोर्ट के अनुसार, कुल छात्रों में से लगभग 79.06% स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं और 11. 5% स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। स्नातक स्तर पर विषयों में सबसे अधिक नामांकन कला (33.5% ) में है, इसके बाद विज्ञान (15.5% ), वाणिज्य (13.9% ) और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी(11. 9% ) का स्थान है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षा का परिमाणात्मक विकास विगत वर्षों में तेजी से हुआ है परन्तु गुणात्मक विकास में ह्रास हुआ है, जो चिन्तनीय है।

आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई विसंगतियों सामने आ रही हैं जो इसके उत्तरदायित्व के निर्वहन पर प्रश्न चिंह लगा रही है, सबसे दुःखद बात तो यह है कि उद्देश्य निर्धारण से लेकर मूल्यांकन तक इन विसंगतियों से उच्च शिक्षा का कोई भी पक्ष अछूता नहीं है। ऐसे में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एक सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा की गुणवत्ता में अभाव के कारण भारतीय छात्र विश्व की मांग के अनुरूप नहीं बन पाते हैं, जो भारतीय शिक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है।

दुःखद है कि अभी तक हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर की अपेक्षा संख्यात्मक विस्तार पर अधिक बल दिया गया है। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षण संस्थाओं जिनमें मानविकी व समाज विज्ञान, विज्ञान, तकनीकी विषय तथा इन्जीनियरिंग की शिक्षा के लिए तमाम शैक्षिक संस्थान खुल गये हैं बिना किसी आवश्यक साधन सुविधाओं के कालेजों संख्या बढती गयी है तथा उनकी कार्य विधियों से शिक्षा का स्तर निम्नकोटि का बनता गया है। इसके साथ ही आर्थिक एवं अन्य साधनों की विकट समस्या हमारे सामने है। आज स्थिति यह है कि अनेक ऐसे स्ववित्तपोषित कॉलेज हैं जहां छात्र केवल प्रवेश लेता है और सत्र के अंत में परीक्षा देने ही आता है तथा उसे परीक्षा में पास होने की गारंटी दी जाती है ऐसे स्ववित्तपोषित कॉलेज में न शिक्षण कार्य होता है और न ही योग्य शिक्षक होते हैं और सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज के अभिभावक ऐसे ही शिक्षण संस्थानों में अपने बालकों का प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

आज सिर्फ उन्हें उच्च शिक्षा की डिग्री मात्र ही लेना है ज्ञान नहीं। ऐसे में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पूरा नियन्त्रण हो। हमें बहुधा यह सुनाई देता है कि आज की शिक्षा से पहली की शिक्षा कहीं ज्यादा अच्छी थी। पहले बी० ए० पास व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखता और बोलता था पर आज के एम० ए० पास व्यक्ति को न तो अंग्रेजी आती है और न हिन्दी। इससे सिद्ध होता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का स्तर पहले से बहुत अधिक गिर गया है। इस पर चिन्ता प्रकट करते हुए आयंगर ने लिखा है **"हमारे ज्ञान या शिक्षा का स्तर वैसे तो कभी ऊँचा नहीं था, पर अब तो यह तीव्र गति से नीचे की ओर जा रहा है।"** उच्च शिक्षा संस्थाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व अध्ययन और अनुसंधान माना गया है परंतु आज अध्ययन की स्थिति तो असंतोष जनक है ही अनुसंधान भी निरर्थक और अनुपयुक्त है।

**उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां•**

- उच्च शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार शहरी क्षेत्रों में अधिक हो रहा है। अतः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर की खाई बढ़ती जा रही है।
- आधुनिक समय में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है जिसके कारण शिक्षण संस्थाएँ व्यवसाय की तरह कार्य कर रही हैं।
- वैश्वीकरण के कारण विदेशी विश्वविद्यालय तेजी से हमारे देश में अपनी शाखाएँ खोल रहे हैं। अतः घरेलू विश्वविद्यालय के समक्ष कड़ी चुनौती है।
- शिक्षा का निजीकरण एक ओर शैक्षणिक विकास की दुहाई देता है वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता के संबंध में यह बड़ी चुनौती है।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की समस्या भी बड़ी चुनौती है। उच्च शिक्षा के समक्ष वैश्विक वातावरण के साथ समायोजन करना भी महत्वपूर्ण चुनौती है।

**21 वीं सदी में उच्च शिक्षा–** 21 वीं सदी अन्तर्राष्ट्रीयता की सदी है इस सदी में शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तरह नई चुनौतियों का सामना करना है। एल्विन टॉपर के अनुसार– **'21वीं सदी के अशिक्षित वह नहीं होंगे जो लिखे और पढ़ सकेंगे बल्कि वह होंगे जो सीख नहीं सकेंगे।'** 21वीं सदी के वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की अपार चुनौतियाँ तथा अनेक अनुत्तरित प्रश्न सुरसा की भाँति मुंह बाये हैं। बाजारवाद, पूंजीवाद तथा भू–मण्डलीकरण के इस दौर में ज्ञान के विस्फोट ने सभी को हक्का बक्का कर दिया है। उच्च शिक्षा का लगातार बढ़ता निजीकरण, निर्धारित मानकों की अनदेखी, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों एवं अभिभावकों का उच्च शिक्षा के प्रति बदलता दृष्टिकोण, आदि उच्च शिक्षा का अंश बन चुके हैं। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश संख्या बहुत होने के बावजूद छात्रों की उपस्थिति अत्यंत कम हैं वहीं कुछ शिक्षकों का पढ़ानें में रूचि न लेना भी एक गंभीर समस्या है परंतु ऐसा भी नहीं है कि सभी शिक्षक उदासीन हैं कुछ अपने कार्य के प्रति सजग हैं पर उन्हें भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्हें कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं।

अतः प्रशासनिक कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाकर इसे दूर किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं में मुख्य रूप से दो तरह के पाठ्यक्रम होने चाहिए पारंपरिकपद्धति के आधार पर जहाँ सैद्धान्तिक विवेचना व्यापक और विशद रूप में पढ़ाई जाए और उसमें केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए जो शिक्षक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

बनना चाहते हैं या शोध कार्यों में जाना चाहते हैं। इस प्रकार की संख्या अत्यंत सीमित होनी चाहिए और जहाँ शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति बहुत बड़ी कसौटियों से गुजरने के बाद की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल प्लेटफार्म की बात कही गयी है। इसके तहत मोबाइल एप, डिजिटल शिक्षा, मूल्यांकन में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। 21 वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड कम्प्यूटर एवं अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा छात्रों को सीखने की लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का महत्व समझा गया तथा इन वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल से शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने का प्रयास किया जा सकता है। वर्तमान सरकार 'स्वयं' और 'दीक्षा' जैसे कार्यक्रमों के डिजिटल संसाधनों के विकास की दिशा में प्रयासरत है। 'स्वयं' एक ऐसा ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है, जिसे मुख्य रूप से भारतवासियों के लिए तैयार किया है. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति, कहीं से भी उच्च गुणवत्ता के शैक्षणिक संसाधनों तक आसानी से पहुंच सकता है. और डिग्री भी पाई जा सकती है। देश के कई विश्वविद्यालय 'स्वयं' के तहत डिग्री प्रदान करते हैं। '21वीं सदी के उच्च शिक्षा के शैक्षणिक स्तर पर सुधार लाने एवं शिक्षा को रोजगारमूलक और समाजोपयोगी बनाने हेतु निम्नांकित सुझावों पर विचार किया जा सकता है–

- शिक्षा व्यवस्था लचीली और गतिशील हो।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं को उपभोक्तावाद, बाजारवाद एवं भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए।
- पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाये, उनमें ऐसे विषय लाये जायें जिनका छात्र के भावी जीवन में वास्तविक उपयोग हो।
- शिक्षित प्रतिभाओं का पलायन रोका जाय तथाउन्हें अपने ही राष्ट्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए शिक्षकों को छात्रों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी सोच बदलना होगा।
- वर्तमान शिक्षा एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाय।
- कैरियर काउंसिलिंग के पाठ्यक्रम की कक्षाएँ एक विषय के रूप में प्रतिदिन संचालित की जायें, जिसमें छात्र व अभिभावक दोनों की हिस्सेदारी हो।
- शिक्षण संस्थाओं में बढ़ते राजनैतिक हस्तक्षेप को रोका जाये।
- उच्च स्तरीय शोध सामग्री सृजित की जाय।
- रोजगारों की मांग के आधार पर शिक्षा दिलाए जाने की व्यवस्था।
- पुस्तकालयों में सामाजिक ज्ञान से परिपूर्ण पत्रिकायें, जर्नल, पुस्तकें, इत्यादि की व्यवस्था हो।
- उच्च शिक्षा मूल्य आधारित हो तथा शिक्षण में राष्ट्र एवं समाज हित को समाहित किया जाये।
- शिक्षण की ऐसी विधियों पर जोर दना चाहिए जिसमें छात्रों का मौलिक विकास हो।
- आने वाले समय का अध्ययन कर रोजगारों की मॉग के आधार पर शिक्षा दिलाए जाने की व्यवस्था हो।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 05, May 2025

- शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को नैतिकता के उच्च स्तर तक पहुँचाने में सक्षम हो।
- मूल्यांकन पद्धति इस प्रकार की हो जिससे मेधावी एवं परिश्रमी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाये। शोध कार्यों पर भी बल दिया जाए।
- शिक्षकों का विद्यार्थियों से अधिक से अधिक सम्पर्क होना चाहिए। उन्हें, उनसे स्नेह होना चाहिए।
- शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाये।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाये एवं शिक्षण संस्थाओं में गुणात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाये।

## संदर्भ ग्रंथ–

1– लाल, रमन बिहारी एवं पालोड़, सुनीता (2017). भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास और उसकी समस्याएं, मेरठः आर लाल बुक डिपो, पृष्ठ संख्या 255–265
2– गोयल, हेमंत कुमार एवं अन्य. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी, मेरठः आर लाल बुक डिपो पृष्ठ संख्या 01
3– गुप्ता, महावीर प्रसाद एवं ममता (2002). भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, आगराः साहित्य प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 148–178
4– सारस्वत, मालती एवं गौतम, एस.एल. भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक समस्याएं, लखनऊः आलोक प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 240–275
5– सक्सैना, एन०आर० स्वरूप (2017). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, मेरठः आर०लाल बुक डिपो।
6- https://pib.gov.in
7- https://www.ugc.gov.in